भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †6431

उत्तर देने की तारीख 02/04/2026

हिंगोली में जनजातीय युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं

†6431. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में जनजातीय छात्र और युवा गरीबी, छात्रावासों की कमी, ख़राब परिवहन सुविधाओं, डिजिटल विभाजन और अपर्याप्त छात्रवृत्ति सहायता के कारण विद्यालयों और महाविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हिंगोली के जनजाति बहुल ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों तक अभिगम अत्यंत सीमित है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय या कौशल केंद्र स्वीकृत किए गए हैं या किए जाने हैं; और

(घ) हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय युवाओं के लिए शैक्षिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने, छात्रवृत्तियों और छात्रावासों का विस्तार करने, डिजिटल समावेशन का संवर्धन करने, कौशल विकास केंद्र स्थापित करने और स्थायी आजीविका और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध रीति से क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): इस परियोजना कार्यालय का परिचालन अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र के दो जिलों नामतः हिंगोली और परभणी को कवर करता है। पूरा परिचालन क्षेत्र बाह्य जनजातीय उप-योजना (ओटीएसपी) के तहत आता है, जिसके कारण परियोजना कार्यालय को अपेक्षाकृत सीमित बजट आवंटन प्राप्त होता है। इस बाधा के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार जनजातीय आबादी के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए व्यक्तिगत और समुदाय आधारित दोनों योजनाओं को लागू कर रही है।

हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, जनजातीय छात्रों और युवाओं के बीच विद्यालय और महाविद्यालय दोनों स्तरों पर स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट दर) नगण्य है। स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दरों को और कम करने तथा स्थिर रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें कक्षा एक से दसवीं तक के छात्रों के लिए *सुवर्ण महोत्सवी छात्रवृत्ति योजना* और उच्चत्तर शिक्षा के लिए भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना के तहत, जो छात्र छात्रावास में रहने की सुविधा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उन्हें आवास, भोजन और शैक्षणिक सामग्री हेतु गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र ₹2,43,000 और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र ₹2,48,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शैक्षिक पहुंच को सहायता प्रदान करने के लिए, परियोजना कार्यालय 5 सरकारी आवासीय आश्रमशालाओं, 7 सहायता प्राप्त आश्रमशालाओं, 2 मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालयों, 6 सरकारी जनजातीय छात्रावासों और 1 सैनिक स्कूल सहित संस्थानों के नेटवर्क की देखरेख करता है। जनजातीय छात्रों में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी आश्रमशालाएं डिजिटल शिक्षण सुविधाओं जैसे टेबलेट प्रयोगशालाओं और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनलों (आईएफपीएस) से सज्जित (लैस) हैं।

कौशल विकास के लिए, *पारधी पैकेज* और एन.बी. योजना जैसी पहलों को लागू किया गया है, जिसके तहत हिंगोली जिले में जनजातीय लाभार्थियों को क्रमशः 30 और 120 लैपटॉप वितरित किए गए हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जमगावां (तालुका कलामनूरी) में एक सरकारी जनजातीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, जिले में पांच अन्य सरकारी आईटीआई और एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कार्यशील हैं, जो तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा के लिए और अधिक अवसर प्रदान करते हैं।

इसके अलावा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना प्रक्रियाधीन है। दिनांक 09.10.2020 के सरकारी संकल्प के अनुसार, कुल 15 एकड़ भूमि आवश्यक है। इसमें से, 7.5 एकड़ जमीन शिवनी (तालुका कलामनूरी) में अधिग्रहित की जा चुकी है। शेष भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और इसके पूरा होने के बाद प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) को प्रस्तुत किया जाएगा।

*****